नईदुनिया

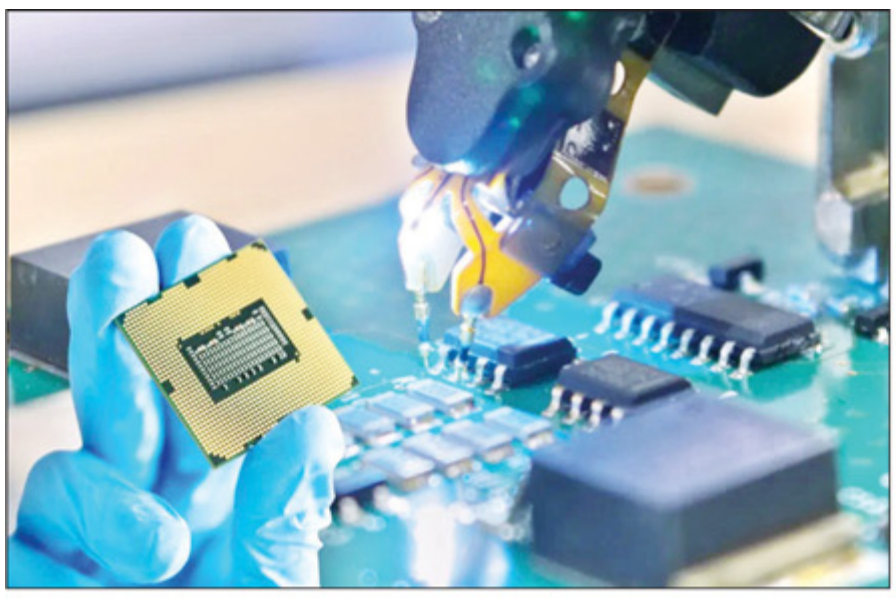

सेमीकंडक्टर में भारत का महादाव, क्या आधी सब्सिडी से पूरा होगा सपना

21 अरब डालर से ज्यादा के प्रोत्साहन के बावजूद, कटौती के बाद निवेशकों को लुभाना बड़ी चुनौती

नई दिल्ली

भारत ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण के क्षेत्र में एक बड़ा और महत्वाकांक्षी रणनीतिक दांव खेला है। 21 अरब डालर से अधिक की विशाल सब्सिडी, जिसमें हाल ही में घोषित 1,27,000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना भी शामिल है, का उद्देश्य देश को 2032 तक वैश्विक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के शीर्ष 5 खिलाड़ियों में स्थापित करना है। इस पहल के तहत अगले पांच वर्षों में 4-6 फैब, 10 ओएसएटी (आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेम्बली ऐंड टेस्ट) इकाइयां और 6-10 कंपाउंड सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने का अनुमान है।

हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहन दरों में हालिया कटौती और अमेरिकी व यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की तुलना में वित्तीय प्रतिबद्धता, इस चिप रेस में भारत की राह को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है। इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की विस्तृत योजना के अनुसार यह विशाल निवेश देश में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और असेम्बली के एक मजबूत तंत्र का निर्माण करेगा। उम्मीद है कि टाटा का फैब संयंत्र 2028 के मध्य तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर देगा, जबकि ओएसएटी/एटीएमपी (असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग ऐंड पैकेजिंग) क्षेत्र में माइक्रोन, केन्स और सीजी पावर जैसे कुछ संयंत्र पहले से ही परिचालन में हैं, जो इस दिशा में शुरुआती सफलता के संकेत देते हैं। शुरुआत में, भारत सरकार निजी क्षेत्र के संयंत्र निवेश पर 50 फीसदी केंद्रीय और अतिरिक्त 20 फीसदी राज्य वित्तीय सहायता प्रदान कर रही थी, जो वैश्विक स्तर पर एक अत्यंत आकर्षक प्रस्ताव था। हालांकि, अब फैब के लिए केंद्र सरकार का प्रोत्साहन घटाकर 35-40 फीसदी और एटीएमपी/ओएसएटी संयंत्रों के लिए 25-35 फीसदी कर दिया गया है।

यह कटौती एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है: क्या यह संशोधित प्रोत्साहन अभी भी निजी क्षेत्र को और अधिक फैब तथा आपूर्तिकर्ताओं का तंत्र स्थापित करने के लिए पर्याप्त रूप से आकर्षक होगा, खासकर जब सेमीकंडक्टर निर्माण में प्रारंभिक निवेश की लागत अत्यधिक होती है वैश्विक स्तर पर देखें तो, भारत की प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अभी भी कई विकसित देशों से पीछे है। अमेरिका का यूएस चिप्स एक्ट 52 अरब डालर का प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करता है, जबकि यूरोपीय संघ में यह सहायता 47 अरब डालर है। इन देशों में कुल निवेश, जिसमें निजी क्षेत्र का योगदान भी शामिल है, खरबों डालर में है (उदाहरण के लिए, अमेरिका में टीएसएमसी, माइक्रोन, इंटेल और सैमसंग का संयुक्त निवेश 650 अरब अनुमानित है)। हालांकि एशिया में, सब्सिडी के लिहाज से भारत की कुल प्रतिबद्धता दक्षिण कोरिया के लगभग बराबर है, जो इस क्षेत्र में एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी है।

न्यूज ब्रीफ

हालीवुड की 81 अरब डालर की मेगा डील पर कोर्ट ने लगाई अस्थायी रोक, कोर्ट ने दोनों कंपनियों को दो सप्ताह तक इस सौदे को आगे नहीं बढ़ाने का आदेश दिया

वाशिंगटन। हालीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी कारोबारी डील पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। पैरामाउंट और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के बीच प्रस्तावित 81 अरब डालर के मेगा मर्जर पर अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने अस्थायी रोक लगा दी है। कोर्ट का यह फैसला उन 12 राज्यों के पक्ष में आया है, जिन्होंने इस सौदे को प्रतिस्पर्धा के लिए खतरा बताते हुए चुनौती दी थी। अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने दोनों कंपनियों को कम से कम दो सप्ताह तक इस सौदे को आगे नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है। राज्यों का तर्क है कि यदि दोनों मीडिया दिग्गज एक हो गए तो हालीवुड में प्रतिस्पर्धा कमजोर होगी, जिसका सीधा असर दर्शकों के विकल्पों और जेब पर पड़ेगा। फेडरल डिस्ट्रिक्ट जज अरासेली मार्टिनेज-ओल्गुइन ने राज्यों की याचिका पर सुनवाई के बाद यह अस्थायी रोक लगाई है, ताकि उन्हें अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने का पर्याप्त समय मिल सके। कैलिफोर्निया की अगुवाई में इन 12 राज्यों ने तर्क दिया है कि विलय से मनोरंजन उद्योग में प्रतिस्पर्धा कम होगी, दर्शकों के पास कंटेंट के विकल्प घटेंगे और केबल टीवी व मनोरंजन सेवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। राज्यों ने पहले दोनों कंपनियों से अदालत के फैसले तक डील को टालने का अनुरोध किया था, लेकिन उनके इनकार के बाद ही कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। फिलहाल यह रोक दो सप्ताह के लिए प्रभावी है। इस अवधि में अदालत मामले की अगली सुनवाई करेगी। यदि कोर्ट को राज्यों की दलीलें मजबूत लगी, तो वह प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी कर सकता है, जिससे इस मेगा डील पर लंबे समय के लिए रोक लग सकती है।

100-200 ही नहीं, 50 रुपये के नकली नोट से भी रहें सतर्क

नई दिल्ली। अक्सर हम बड़ी खरीदारी में ही नोटों की जांच करते हैं, लेकिन अब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 50 रुपये जैसे छोटे नोटों पर भी सतर्क रहने की अपील की है। बाजार में 50 रुपये के नकली नोटों के चलन बढ़ने की खबरों के बीच आरबीआई ने आम जनता के लिए असली नोटों की पहचान करने के कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स साझा किए हैं ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके। आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है। आरबीआई के अनुसार, लोग अक्सर 50, 20 या 10 रुपये के नोटों को बिना जांचे जेब में रख लेते हैं, जिसका फायदा ठग उठाते हैं। असली 50 रुपये के नोट की पहचान के लिए ध्यान दें- सी-थ्रू फीचर : नोट के नीचे बाईं ओर 50 का एक पारदर्शी अंक होता है, जो रोशनी में रखने पर साफ दिखाई देता है।, देवनागरी में 50 : नोट पर 50 का अंक हिंदी (देवनागरी लिपि) में भी अंकित होता है।, महात्मा गांधी का चित्र : नोट के बीचों-बीच महात्मा गांधी की स्पष्ट तस्वीर छपी होती है।, गवर्नर के हस्ताक्षर : नोट के दाईं ओर का लोगो, गवर्नर के हस्ताक्षर और भुगतान का वादा (गारंटी क्लाज) मौजूद होता है।, बढ़ते क्रम में सीरियल नंबर : ऊपर बाईं और नीचे दाईं ओर लिखे सीरियल नंबर के अंक छोटे से बड़े आकार में बढ़ते क्रम में होते हैं।, अशोक स्तंभ : नोट के नीचे दाईं ओर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का प्रतीक बना होता है।

रिलायंस का कैंपा कोल्ड ड्रिंक बाजार में छाया, बना तीसरा खिलाड़ी, कई बाजारों में दोहरे अंकों की हिस्सेदारी, कोका-कोला व पेप्सिको को कड़ी टक्कर

नई दिल्ली। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (आरसीपीएल) का साफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैंपा भारतीय बाजार में तेजी से पैठ बना रहा है। अब यह देश के गैर-मादक रेडी-टू-ड्रिंक (एनएआरटीडी) पेय बाजार की तीसरी सबसे बड़ी खिलाड़ी बन गई है, जो कोका-कोला और पेप्सिको जैसे स्थापित ब्रांडों को कड़ी चुनौती दे रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अनुसार, जून तिमाही में पेय कारोबार से लगभग 2,900 करोड़ रुपए का राजस्व मिला, जो उल्लेखनीय वृद्धि है। कैंपा और इडिपेंडेंस जैसे ब्रांडों की बदौलत कंपनी ने कई क्षेत्रीय बाजारों में पहले ही दोहरे अंकों की बाजार हिस्सेदारी हासिल कर ली है। 2023 में दोबारा लान्च के बाद, कैंपा ने आक्रामक मूल्य निर्धारण, व्यापक वितरण नेटवर्क और उत्पाद विविधता के दम पर तेजी से विस्तार किया है। कंपनी ने कोला के अलावा लेमन, आरेंज और एनर्जी ड्रिंक जैसे उत्पादों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है।

सब्सक्रिप्शन के लिए खुला मेटालिक टेक्नोफोर्ज का आईपीओ, 28 जुलाई को हो सकती है लिस्टिंग

नई दिल्ली

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी मेटालिक टेक्नोफोर्ज का 49.96 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए लान्च कर दिया गया। इस आईपीओ में 23 जुलाई तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद 24 जुलाई को शेयरों का अलाटमेंट किया जाएगा, जबकि 27 जुलाई को अलाटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर 28 जुलाई को एनएसई के एसएमई प्लेटफार्म पर लिस्ट हो सकते हैं। पहले दिन दोपहर 11:30 बजे तक ये आईपीओ 16 प्रतिशत सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 72 रुपये से लेकर 77 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लाट साइज 1,600 शेयर का है। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स को दो लाट यानी 3,200 शेयरों के लिए बोली लगाना होगा, जिसके लिए उन्हें 2,46,400 रुपये का निवेश करना होगा। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 64.88 लाख नए शेयर जारी हो रहे हैं।

इस आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए 47.35 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इसके अलावा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए 33.29 प्रतिशत हिस्सा और नान इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए 14.30 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। इसके अलावा मार्केट मेकर के लिए 5.06 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इस इश्यू के लिए स्मार्ट हारिजन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है, जबकि बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है। वहीं श्रेणी शेयर्स लिमिटेड कंपनी का मार्केट मेकर है।

मेटालिक टेक्नोफोर्जव की वित्तीय स्थिति की बात करें तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्राप्सेक्टस (डीआरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी को 4.26 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 9.03 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। वहीं पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को 12.36 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ।

इस दौरान कंपनी की राजस्व प्राप्ति में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में इसे 51.50 करोड़ का कुल राजस्व प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 75.64 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। वहीं पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी को 97.98 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो चुका था। इस अवधि में कंपनी पर लदे कर्ज का बोझ भी लगातार बढ़ता गया। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में कंपनी पर 10.81 करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 27.97 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। वहीं पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें, तो इस दौरान कंपनी पर लदे कर्ज का बोझ 31.78 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया।

इस अवधि में कंपनी के नेटवर्थ में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 में ये 7.72 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो 2024-25 में बढ़ कर 17.40 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का नेटवर्थ उछल कर 33.42 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। कंपनी के रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो इस अवधि में कंपनी इस मोर्चे पर उतार चढ़ाव होता रहा। वित्त वर्ष 2023-24 में ये 7.37 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो 2024-25 में बढ़ कर 16.40 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का रिजर्व और सरप्लस मामूली गिरावट के साथ 15.92 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया था।

इसी तरह ईबीआईटीडीए (अर्निंग बिफोर इंट्रेस्ट, टैक्सेज, डिप्रेशिएशंस एंड एमार्टाइजेशन) 2023-24 में 7.29 करोड़ रुपये के स्तर पर था, जो 2024-25 में बढ़ कर 16.08 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। वहीं पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का ईबीआईटीडीए 21.95 करोड़ रुपये के स्तर पर था।

अमेरिका का कनाडा पर व्यापारिक वार, अधिकांश आयात पर 50 फीसदी शुल्क

वाशिंगटन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आयात होने वाली अधिकतर वस्तुओं पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा कर दोनों देशों के व्यापार संबंधों में नया तनाव पैदा कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने कनाडा पर अमेरिकी वाहनों, मादक पेय और डेयरी उत्पादों के साथ अनुचित भेदभाव करने का आरोप लगाया है।

आर्थिक अनिश्चितता और दोनों देशों के संबंधों में तनाव बढ़ने की आशंका

इस कदम से आर्थिक अनिश्चितता बढ़ने और मुद्रास्फीति में वृद्धि की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि चीन के अलावा कनाडा उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने ट्रंप द्वारा लगाए गए पिछले शुल्कों के जवाब में प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की थी, और उसे अब इसके लिए जवाबदेह ठहराया जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 1930 के व्यापार अधिनियम की धारा 338 के तहत इन शुल्कों को लागू करने के लिए तीन घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष कई डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस धारा को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था, उनका तर्क था कि राष्ट्रपति इसका उपयोग अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए कर सकते हैं। नए 50 प्रतिशत शुल्क के दायरे से ऊर्जा उत्पाद, पोटाश, मछली और महत्वपूर्ण खनिजों को बाहर रखा गया है। हालांकि, इसमें वे वस्तुएं शामिल होंगी जिन्हें पहले अमेरिका-मैक्सिको-कनाडा समझौते (यूएसएमसीए) के तहत आयात शुल्क से छूट प्राप्त थी। वर्ष 2020 में लागू हुए इस व्यापार समझौते की समीक्षा और नए सिरे से वार्ता शुरू हुई है, जो 2036 तक इसकी अवधि बढ़ाने की दिशा तय कर सकती है। व्हाइट हाउस के तथ्य पत्रक के अनुसार, ये शुल्क 30 दिन बाद प्रभावी होंगे।

एसीएमई सोलर ने सेकी के साथ किया बिजली खरीद समझौता

नई दिल्ली। एसीएमई सोलर होल्डिंग्स ने 300 मेगावाट की अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) से जुड़ी पवन-सौर हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम (सेकी) के साथ बिजली खरीद समझौता (पीपीए) किया है। कंपनी ने मंगलवार को बयान में कहा कि उसकी अनुषंगी कंपनी एसीएमई रिन्यूटेक फिफ्थ प्राइवेट लिमिटेड ने इस परियोजना के लिए सेकी के साथ 25 वर्ष की अवधि का बिजली खरीद समझौता किया है। बयान के अनुसार इस परियोजना के लिए शुल्क को केंद्रीय और राज्य नियामकों से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।

सर्राफा बाजार में महंगा हुआ सोना, चांदी की भी बढ़ी चमक

नई दिल्ली

घरेलू सर्राफा बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान तेजी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। भाव में आए उछाल के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,43,470 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,43,620 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना 1,31,510 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,31,660 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में भी प्रति किलोग्राम 5,200 रुपये की तेजी आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में 2,35,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है।

दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,43,620 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,31,660 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,43,470 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,31,510 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,43,520 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,31,560 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,43,470 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,31,510 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह

कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,43,470 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,31,510 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,520 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,31,560 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,43,620 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,31,660 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,520 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,31,560 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,43,620 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,31,660 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी सोने के भाव में तेजी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 1,43,470 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सर्राफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 1,31,510 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत, एशिया में तेजी का रुख

नई दिल्ली

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान गिरावट के साथ बंद हुए थे। हालांकि डाउ जान्स फ्यूचर्स बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान मिला-जुला कारोबार होता रहा। वहीं एशियाई बाजार में आमतौर पर तेजी का रुख बना हुआ है।

अमेरिका स्टाक मार्केट पिछले सत्र के दौरान गिरावट के साथ बंद हुआ। डाउ जान्स इंडस्ट्रियल एवरेज 307.16 अंक यानी 0.59 प्रतिशत टूट कर 51,839.26 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह एस एंड पी 500 इंडेक्स ने 0.19 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 7,443.28 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा नैस्डेक 0.05 प्रतिशत फिसल कर 25,508.07 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं डाउ जान्स फ्यूचर्स फिलहाल 116.42 अंक 0.22 प्रतिशत की बढ़त के साथ 51,955.68 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

यूरोपीय बाजार पिछले सत्र के दौरान मिले-जुले परिणाम के साथ बंद हुए। एफटीएसई इंडेक्स 75.61 अंक यानी 0.72 प्रतिशत लुढ़क कर 10,524.76 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसके विपरीत सीएसी इंडेक्स ने 0.02 प्रतिशत की सांकेतिक बढ़त के साथ 8,340.11 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा नैस्डेक 0.06 प्रतिशत की मामूली तेजी के साथ 24,846.69 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

एशियाई बाजार में आमतौर पर खरीदारी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। एशिया के नौ बाजार में से आठ के सूचकांक मजबूती के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि सिर्फ एक सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में बना हुआ है। एशियाई बाजार में इकलौता गिफ्ट निफ्टी 0.17 प्रतिशत टूट कर 24,242 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

दूसरी ओर, निक्केई इंडेक्स 1,737.88 अंक यानी 2.71 प्रतिशत की तेजी के साथ 65,879 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसी तरह जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स 1.17 प्रतिशत उछल कर 6,304.71 अंक के स्तर पर आ गया है। कोस्पी इंडेक्स में जबरदस्त मजबूती नजर आ रही है। फिलहाल यह सूचकांक 307.98 अंक यानी 4.73 प्रतिशत उछल कर 6,824.25 अंक के स्तर पर पहुंच गया है।

ताइवान वेटेड इंडेक्स ने भी जोरदार छलांग लगाई है। फिलहाल यह सूचकांक 1,353.36 अंक यानी 3.19 प्रतिशत की उछाल के साथ 43,803.06 अंक के स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.77 प्रतिशत की बढ़त के साथ 5,541.20 अंक के स्तर पर, शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.62 प्रतिशत की मजबूती के साथ 3,819.66 अंक के स्तर पर, हैंग सेंग इंडेक्स 0.14 प्रतिशत उछल कर 25,177 अंक के स्तर पर और सेट कंपोजिट इंडेक्स 0.07 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,647.10 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।